

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

(8)

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग-1

देहरादून दिनांक 28 फरवरी, 2011

विषय:-वित्तीय वर्ष 2010-11 में राज्य सैक्टर के अन्तर्गत स्पेशल कम्पोनेंट प्लान की योजनाओं पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-391/2-6-449(स्पेशल कम्पोनेंट प्लान)/2009, दिनांक 20 नवम्बर, 2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हरिद्वार के वार्ड नम्बर-01 मौहल्ला कड़च्छ का पर्यटन विकास हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन ₹ 54.92 लाख तथा उत्तरकाशी के महासु मंदिर भकोली (नौगांव) के परिसर का सौन्दर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन ₹ 21.43 लाख के परीक्षणोपरान्त टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गयी धनराशि क्रमशः ₹ 48.39 लाख (₹ अड़तालीस लाख उन्नतालीस हजार मात्र) तथा ₹ 20.28 लाख (₹ बीस लाख अट्ठाईस हजार मात्र) की धनराशि अर्थात् कुल ₹ 68.67 लाख (₹ अड़सठ लाख सड़सठ हजार मात्र) की धनराशि के लागत के प्राक्कलनों पर प्रशासकीय स्वीकृति देते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में राज्य सैक्टर की अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 20.00 लाख (₹ बीस लाख मात्र) तथा ₹ 10.00 लाख (₹ दस लाख मात्र) अर्थात् कुल ₹ 30.00 लाख (₹ तीस लाख मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के हेतु पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धि की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावाली 2008 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

- (3) कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।
- (4) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य को प्रारम्भ न किया जाय।
- (5) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्यदायी संस्था से वित्त विभाग के द्वारा निर्गत मानक अनुबन्ध निष्पादित करा लिया जायेगा।
- (6) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।
- (7) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।
- (8) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।
- (9) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।
- (10) निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाये, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।
- (11) कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी तथा बाढ़ व नदी के बहाव आदि से सम्बन्धित सभी बिन्दुओं का परीक्षण निर्माण एजेन्सी द्वारा निर्माण से पूर्व कर लिया जाएगा जिससे भविष्य में किसी प्रकार की समस्या न हो।
- (12) कार्य प्रारम्भ के समय सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी कार्यस्थल पर इस आशय का एक साईन बोर्ड स्थापित करेगा कि उक्त योजना/कार्य पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड के सौजन्य से किया जा रहा है, योजना प्रारम्भ करने का समय, इसकी लागत, पूर्ण करने का समय तथा कार्यदायी संस्था का विवरण भी अंकित किया जायेगा। सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी उक्त कार्य का समय-समय पर भौतिक निरीक्षण कर कार्य की भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह शासन को अवगत करायेगें एवं कार्य पूर्ण होने की सूचना व योजना का फोटोग्राफ्स आवश्यक शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध करायेगा।
- (13) उक्त स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31-03-2011 तक पूर्ण उपयोग कर धनराशि की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा तदोपरान्त ही अवशेष अथवा दूसरी किस्त अवमुक्त की जायेगी।



(14) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047 /XIV-21(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(15) उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 के अनुदान संख्या-30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय-80-सामान्य-आयोजनागत-104-सम्बर्द्धन तथा प्रचार-04-पर्यटन विकास की नई योजनायें(राज्य सेक्टर)-49-पर्यटन विकास की नई योजनायें-24-वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

(16) उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0-770/XXVII(2)/2011, दिनांक 22 फरवरी, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 123 /VI(1)/2011-2(3)2008, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
- 3- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
- 4- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी/हरिद्वार।
- 5- निजी सचिव-मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन मा0 मुख्यमंत्री जी के अवगतार्थ।
- 6- निजी सचिव-मा0 पर्यटन मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन मा0 पर्यटन मंत्री जी के अवगतार्थ।
- 7- निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन मुख्य सचिव महोदय के अवगतार्थ।
- 8- सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 9- अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 10- वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
- 11- जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तरकाशी/हरिद्वार।
- 12- एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
- 13- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)

अनुसचिव।

21/2/2011